हिमाचल का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक समाचार पत्र

आप का सामना

हक़ीक़त से

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब,चंडीगढ़,दिल्ली, में प्रसारित

पोस्टल रजि.नंबर एचपी/33/ एसएमएल
(31 दिसंबर 2024 तक मान्य)

वर्ष- 14 अंक-29 शिमला शुक्रवार,03 से 09 मई 2024 आरएनआई एचपीएचआईएन/2010/41180 कुल पृष्ठ-6 मूल्य- 5 रू०

आईपीए अधिकारी अतुल वर्मा बने हिमाचल के नए पुलिस महानिदेशक

अकसा शिमला। हिमाचल सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. अतुल वर्मा को हिमाचल पुलिस का नया मुखिया बनाया है।

निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद सरकार ने तैनाती की है। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए है।

अतुल वर्मा मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं।

वह दो महीने पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस हिमाचल लौटे हैं। राज्य सरकार ने एक मार्च को उन्हें सीआइडी प्रमुख बनाया था। अतुल वर्मा 31 मई 2025 को रिटायर होंगे।

सुबह के वक्त उनकी तैनाती के आद. `श जारी किए गए और दोपहर बाद डॉ. वर्मा ने अपना पदभार भी संभाल लिया है। इस दौरान मुख्यालय ने उनका पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

दो आईपीएस को किया सुपरसीड

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो सीनियर आईपीएस को सुपरसीड करते हुए डॉ. वर्मा की ताजपोशी की है। डॉ. वर्मा से सीनियर ढ्ढक्कस् 1989 के डीजी जेल एसआर ओझा और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे 1990 बैच के ढ्ढक्कस् श्याम भगत नेगी है।

एक दिन पहले रिटायर हुए कुंडू

डीजीपी पद से संजय कुंडू रिटायर हुए हैं।

उनकी सेवानिवृत होने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने डॉ. अतुल वर्मा पर भरोसा जताया है। इससे पहले हिमाचल सरकार ने यूपीएससी को तीन सीनियर आईपीएस का पैनल भेजा था।

इनमें एसआर ओझा, श्याम भगत नेगी और डॉ. वर्मा का नाम शामिल था।

1992 में करियर की शुरुआत की

अतुल वर्मा ने एमबीबीएस और एमबीए की पढ़ाई कर रखी है। 11 अक्टूबर 1992 को उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और विभिन्न पदों पर सेवाएं दी।

उन्होंने पुलिस महानिदेशक राज्य गुप्तचर विभाग, पुलिस महानिदेशक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजिलेंस, केंद्र में विशेष सचिव गृह जैसे पदों पर सेवाएं दी है।

सेंसर युक्त फायर अलर्ट सिस्टम वनों में आग लगने से पहले ही सावधान कर देगा, ट्रायल शुरू

आकसा मंडी। हिमाचल प्रदेश के वनों में आग लगने से पहले ही सेंसर युक्त फायर अलर्ट सिस्टम सावधान कर देगा। इससे वनों में आग लगने से पहले ही उसे रोका जा सकेगा। दिल्ली के एक स्टार्टअप के तहत बना यह उपकरण वनों में आग लगने से पहले ही वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों सहित अन्य कई स्वयंसेवियों को अलर्ट कर देगा।

इस उपकरण को मंडी वन रेंज में आग लगने की .ष्टि से अति संवेदनशील शहर के आसपास लगते वनों में ट्रायल के तौर पर लगाया गया है। भविष्य में अगर यह ट्रायल सफल रहता है तो विभाग इसे लागू करेगा।

इससे जहां अमूल्य वन संपदा को जलने से बचाया जा सकता है। वहीं, इससे असंख्य जीव जंतुओं की जानें बच सकेंगी।

बता दें कि जिला मंडी सहित प्रदेशभर में गर्मियों के मौसम में हर बार वनों में आग लगने की घटनाएं होती हैं।

इसमें वन संपदा सहित कई जीव–जंतु बेमौत मारे जाते हैं।

अरण्यपाल मंडी अजीत कुमार ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस डिवाइस को मंडी रेंज में तीन जगहों पर स्थापित किया गया है। आने वाले समय में ही इसकी सफलता का पता चल पाएगा।

इसके आधार पर इसे अन्य स्थानों पर स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा।

इस प्रकार काम करेगा उपकरण

सेंसर युक्त इस डिवाइस को दिल्ली के एक स्टार्टअप ने बनाया है। डिवाइस आर्द्रता, तापमान और कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा के आधार संकेतों को रिकॉर्ड करता रहता है और वन विभाग को संकेत देता है कि आग लगने कि कितनी संभावना है। मंडी में इस डिवाइस को आईसीआईसीआई फाउंडेशन के सहयोग से तीन स्थानों पर लगाया गया है। इससे गर्मियों के दिनों में डाटा एकत्र होगा और इससे वनों में आग लगने का पता चल पाएगा।

कांग्रेस ने हमीरपुर से सतपाल रायजादा कांगड़ा से आनंद शर्मा को दी टिकट

आकसा शिमला । हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को कांगड़ा संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। मंगलवार शाम को कांग्रेस हाईकमान ने जिला कांगड़ा के सभी विधायकों की सहमति लेने के बाद ब्राह्मण नेता आनंद शर्मा को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की। राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता रह चुके आनंद का अब भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज से मुकाबला होगा। वहीं, हमीरपुर संसदीय सीट से पार्टी ने पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को प्रत्याशी बनाया है।

रायजादा को प्रत्याशी बनाए जाने की शुरू से ही अटकले थीं, लेकिन पार्टी बीच में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर भी विचार कर रही थी। मुकेश के चुनाव लडऩे से इन्कार करने के बाद पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनौती देने के लिए ऊना से पूर्व विधायक रहे सतपाल रायजादा को ही चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल की ओर से दोनों प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की गई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राजधानी शिमला से संबंध रखने वाले आनंद शर्मा अभी तक राज्यसभा के मार्फत ही मनमोहन सिंह की दो सरकारों में केंद्रीय मंत्री का पद संभाल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से दो–दो बार राज्यसभा सदस्य रह चुके आनंद की छवि राष्ट्रीय स्तर के नेता की रही है। इससे पहले आनंद शर्मा शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से 1982 चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें भाजपा के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा था।

71 वषीय आनंद की मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ काफी नजदीकियां हैं। सुक्खू को प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ाने में आनंद शर्मा की अहम भूमिका मानी जाती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को पूरी गंभीरता से लडऩे का फैसला लिया है। किसी भी सीट पर कमजोर प्रत्याशी नहीं देने की योजना के तहत ही आनंद शर्मा का चयन कांगड़ा संसदीय सीट से चुनाव लडऩे के लिए किया गया है। आनंद शर्मा को चुनाव लड़ाने से पहले पार्टी हाईकमान ने सभी विधायकों की राय भी ली है। प्रदेश कांग्रेस की सहमति होने के बाद पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर सभी को चौंकाते हुए भाजपा को भी कड़ी चुनौती दे दी है। उधर, संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से कांग्रेस ने सतपाल रायजादा को प्रत्याशी बनाकर मुख्यमंत्री सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश और कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की जवाबदेही भी तय कर दी है। हमीरपुर इन तीनों बड़े नेताओं का गृह संसदीय क्षेत्र है। दूसरी ओर, धर्मशाला, बड़सर और लाहौल–स्पीति में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने को लेकर मंथन जारी है। संभावित है कि एक–दो दिन के भीतर इन प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो जाएगी।

कौन हैं आनंद शर्मा

5 जनवरी, 1953 में शिमला में जन्मे आनंद शर्मा ने आरपीसीएएडीबी कॉलेज (अब आरकेएमवी) और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। एनएसयूआई के संस्थापक सदस्य रहे आनंद शर्मा 2006 से 2009 तक विदेश राज्य मंत्री, 2009 से 0214 तक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग व कपड़ा मंत्री, 8 जून 2014 से 2022 तक विपक्ष में उपनेता रहे।

कौन हैं सतपाल रायजादा

23 अगस्त, 1970 को जन्म सतपाल रायजादा ने ऊना के सरकारी स्कूल से दसवीं पास की थी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रायजादा ने 2012 में पहली बार ऊना से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ती को उन्होंने 3,196 वोटों से हराया था। रायजादा प्रदेश राटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।

सोलन और सिरमौर के नेताओं का ही दबदबा रहा शिमला संसदीय सीट पर, जीत और हार में शिमला जिले की अहम भूमिका

आकसा शिमला। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र आरक्षित संसदीय क्षेत्र का नाम तो बेशक शिमला है लेकिन इस सीट पर दबदबा सोलन और सिरमौर जिला के नेताओं का ही रहा है। वर्ष 1952 से 2019 तक सिर्फ एक बार जिला शिमला को सांसद का पद मिला है। 38 वर्ष तक सोलन और 30 वर्ष तक सिरमौर के नेताओं ने शिमला संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनी. तिक दलों ने शिमला जिला की जगह सोलन–सिरमौर के नेताओं को ही प्रत्याशी बनाने में अधिमान दिया है। इस बार भी भाजपा और कांग्रेस ने सात विधानसभा क्षेत्रों वाले शिमला जिले से अपने प्रत्याशी नहीं दिए हैं। भाजपा ने सिरमौर तो कांग्रेस ने सोलन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं।

जीत और हार में शिमला जिले की अहम भूमिका

शिमला संसदीय सीट से चाहे दोनों बड़े राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिए हैं, लेकिन प्रत्याशियों की जीत और हार में शिमला जिला की भूमिका अहम रहती है। प्रत्याशियों को जीत की दहलीज लांघने के लिए शिमला से मिलने वाले मतों का बड़ा आसरा होता है। जिले में सात विधानसभा क्षेत्र आते हैं जबकि सोलन और सिरमौर में पांच–पांच विधानसभा हैं।

लगातार छह बार सांसद रहे हैं सुल्तानपुरी

शिमला संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व सोलन जिले के .ष्ण दत्त सुल्तानपुरी ने किया है। सुल्तानपुरी 1980 से 1998 तक लगातार छह बार सांसद रहे। सिरमौर के प्रताप सिंह दो बार सांसद रहे। इनका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा। वहीं, सोलन जिले से ही कर्नल धनीराम शांडिल दो बार सांसद रहे और इनका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा। सोलन जिला के वीरेंद्र कश्यप दो बार सांसद रहे, इनका कार्यकाल भी दस वर्ष रहा।

इस बार भी सोलन और सिरमौर से हैं दोनों प्रत्याशी

भाजपा ने सिरमौर से वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। सोलन जिले से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक विनोद सुल्तानपुरी पर दांव खेला है। ऐसे में अपने–अपने गृह जिला के मतों के अलावा शिमला जिले की सात सीटों में बढ़त लेने वाले पार्टी प्रत्याशी के लिए ही दिल्ली पहुंचने की राह आसान होगी।

वर्ष 1977 में शिमला के बालक राम कश्यप चुने गए थे सांसद

1977 के चुनाव में शिमला निवासी बालक राम कश्यप जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। शिमला से एक मात्र सांसद बालक राम का कार्यकाल भी ढाई वर्ष रहा।1980 के बाद से सभी चुनावों में सोलन और सिरमौर जिले से ही भाजपा और कांग्रेस के सांसद बनते आए हैं।

सिरमौर के पांच, सोलन जिले के चार नेता पहुंचे हैं संसद

सिरमौर के पांच और सोलन से चार नेता अभी तक संसद तक पहुंच चुके हैं। सोलन से संबंध रखने वाले डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल (सेवानिवृत्त) ने 1999 में हिमाचल विकास कांग्रेस के टिकट पर सिरमौर जिले से कांग्रेस उम्मीदवार गंगू राम मुसाफिर को हराकर शिमला संसदीय सीट जीती थी। शांडिल ने कांग्रेस का एकाधिक. ार तोड़ते हुए जीत दर्ज की थी। बाद में शांडिल कांग्रेस में शामिल हो गए।

धर्म और जाति की राजनीति कर रही भाजपा मुद्दों की जगह : नरेश चौहान

आकसा शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार का दस वर्षों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। अब भाजपा नेता असली मुद्दों पर बात न करके धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग असली मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई क्यों बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री के दोस्त एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जबकि जनता को पांच किलो आटा देकर अहसान जताया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए।

15 महीनों के कामों पर चर्चा के लिए तैयार कांग्रेस

नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान राज्य सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि भाजपा नेता राजनीति को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं।

सरकार ने मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में दो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किए हैं। दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है।

सेब किलो के आधार पर बेचे जाने की नीति लाई गई। राज्य सरकार ने सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ऐतिहा. सिक डेढ़ रुपये की बढ़ोतरी करने के साथ–साथ सीए स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम किया और अब अगले सीजन से सेब यूनिवर्सल कार्टन में बिकने जा रहा है।

18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह सम्मान निधि देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही 1000 और 1150 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली प्रदेश की 2.74 लाख महिलाओं को भी 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है।

नरेश चौहान ने कहा कि कहा कि आपदा के दौरान राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया जबकि भाजपा आपदा के दौरान गुम रही।

जब हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया, तो भाजपा के किसी भी विधायक ने साथ नहीं दिया। पूर्व भाजपा सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को खजाना खाली मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं।

कोरोना संकट के दौरान बिंदल ने क्यों छोड़ा प्रदेश अध्यक्ष पद

नरेश चौहान ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल पर वर्तमान राज्य सरकार पर नाकामी के आरोप लगाने के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना संकट के दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा, यह बताना चाहिए।

जनता जानती है कि पिछली सरकार में उन्हें आरोपों के चलते हटाया गया। कर्ज लेने, भर्ती परीक्षा के पेपर बेचने का मॉडल लाए जयराम

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल में कर्ज लेने और भर्ती परीक्षा के पेपर बेचने का मॉडल लेकर आए हैं।

प्रदेश की जनता उन्हें इन दो कार्यों के लिए हमेशा याद रखेगी।

भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर बिका और हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग में पेपरों की नीलामी होती रही।

उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख है। षड्यंत्र कर वह प्रदेश सरकार को गिराने के असफल प्रयास में लगे हुए हैं।

हिमाचल में कांग्रेस की लड़ाई बिकाऊ विधायकों के खिलाफ : मुख्यमंत्री

आकसा शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को फिर सियासी निशाना साधा है। नादौन में पत्रकारा. ं से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। चार जून को प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के जयराम ठाकुर के दावे पर सीएम सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष झूठ व डर के सहारे सत्ता पाना चाह रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। वह धैर्य रखें, 4 जून को जनता का जवाब भाजपा को मिल जाएगा।

जयराम ठाकुर का गणित बेहद कमजोर

हिमाचल में कांग्रेस की लड़ाई बिकाऊ विधायकों और लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ है। कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों को निश्चित तौर पर भाजपा ने खरीदा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम झूठ का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जनता में उनकी पोल खुल चुकी है। जयराम का गणित बेहद कमजोर है, कांग्रेस सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर जनता की अदालत में जाएगी। जनता की सेवा जिसने की होगी, उसे फिर सत्ता में आने का मौका मिलेगा। जयराम नहीं चाहते थे कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम, महिलाओं को 1500 रुपये, मनरेगा कर्मियों को 60 रुपये बढ़ी हुई दिहाड़ी, किसानों को दूध पर एमएसपी व कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिले, इसलिए वह नोटों के दम पर सरकार गिराने की साजिश रचने में लगे रहते हैं।

पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनंद शर्मा कांगड़ा से क्यों नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा कांगड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतर सकते। वह तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाले हैं और पूरा राज्य उनका घर है। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, आनंद शर्मा को कांगड़ा से टिकट मिली है। वह अच्छे वक्ता हैं, उनकी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ व समझ है। वह राष्ट्रीय स्तर पर जाने–पहचाने चेहरे हैं। संसद में उनकी आवाज गूंजने पर हिमाचल को लाभ होगा।

आनंद शर्मा पार्टी के बड़े चेहरे

आनंद शर्मा ने पूर्व यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते कांगड़ा के लिए बड़े प्रोजेक्ट व कार्यालय लाए हैं। कांगड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंदौरा में डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लागत का इंडस्ट्रियल पार्क, चाय बागवानों के लिए नेशनल टी बोर्ड का रीजनल सेंटर आनंद शर्मा ने खुलवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद पार्टी का बड़ा चेहरा हैं, वह संसद में कांग्रेस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेंगे।

भाजपा के तीनों सासंद प्रदेश में आई इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के दौरान केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज दिलाने में विफल रहे। आनंद शर्मा केंद्र में बनने वाली कांग्रेस सरकार में अहम भूमिका निभाकर हिमाचल के लिए विशेष पैकेज लाएंगे।

विधायकों को बिकाऊ बताने वाले सीएम सुक्खू बताएं रंजीत राणा को कितने में खरीदा – राकेश जम्वाल

आकसा हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुक्खू विधायकों को बिकाऊ बता रहे हैं, लेकिन वह यह बताएं कि कैप्टन रंजीत राणा समेत भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को कितने में खरीदा है। आरोप लगाना एक बात है। मुख्यमंत्री सुक्खू की तानाशाही से विधायक थे। चार जून को मुख्यमंत्री को जवाब मिल जाएगा।

भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता एवं सुजानपुर चुनाव प्रभारी विधायक राकेश जम्वाल ने हमीरपुर पत्रकार वार्ता में सीएम सुक्खू पर यह निशाना साधा है।

आनंद शर्मा का हिमाचल से नहीं रहा ज्यादा सरोकार

विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव से कोई सबक नहीं लिया है। कांग्रेस लोकसभा चुनावों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही। दिल्ली से मनु सिंघवी को लाकर चुनाव लड़वाया और राज्यसभा में हार गए। अब इन्होंने कांगड़ा से आनंद शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। केंद्र में कांग्रेस के बहुत बड़े–बड़े ओ. हदों पर रह चुके आनंद शर्मा केंद्र सरकार में मंत्री तक भी रहे हैं, लेकिन हमने देखा है प्रदेश के साथ कोई ज्यादा सरोकार उनका आज तक नहीं रहा। 40 साल पहले शिमला से उन्होंने एक विधानसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें वह हार गए थे। ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कहीं पर भी लोकसभा चुनावों को जीतने की .ष्टि से नहीं लड़ रही बल्कि मुख्यमंत्री केवल अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के काम में लगे हुए हैं।विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश में कांग्रेस सरकार को विधायकों की कितनी सख्त जरूरत हिमाचल प्रदेश में है यह किसी से छुपा नहीं है इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने लोक सभा चुनाव के लिए दो जगह से दो विधायकों को उतार दिया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के बीच आपसी संबंध इनका कैसा है। बड़ी जद्दोजहद से राजा वीरभद्र सिंह किस पुत्र विक्रमादित्य सिंह मंत्री बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में उतारा है। यह इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस किस नजरिए से लोकसभा चुनावों को देख रही है। चार जून को जैसे ही परिणाम आएंगे वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी उदल–पुथल होगी।

इस अवसर पर पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, प्रदेश सचिव उपचुनाव के सह प्रभारी नरेंद्र अत्री, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, जिला महामंत्री अजय रिंटू शर्मा तथा जिला मीडिया प्रभारी विकास उपस्थित रहे।

केंद्र से मिले 2,000 करोड़, प्रदेश ने खर्च किए केवल 1,720 करोड़ – रणधीर शर्मा

आकसा शिमला। भाजपा के मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रा.तिक आपदा आने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटे।

सच्चाई यह है कि आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से प्रदेश की अलग–अलग किस्तों में 2,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की। प्रदेश सरकार ने हिमाचल की जनता से 252 करोड़ रुपये आपदा राहत कोष के नाम पर भी जमा किए। अभी तक हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 1,720 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं।

रणधीर शर्मा ने कहा कि 7 लाख रुपये मकान बनाने की घोषणा करने वाला. ं ने अभी तक जनता को 3 लाख रुपये ही इस सरकार ने दिए, जिन लोगों की पूरी जमीन बर्बाद हो गई, उनको नई जमीन देने का वादा कर भी अभी तक किसी को जमीन नहीं दी गई। कांग्रेस सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक भी किस्त नहीं दी। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में 40 प्रतिशत अधिक टैक्स लगाया है। मिल्क सेस के नाम पर 10 रुपये शराब की बोतल महंगी की, उससे 90 करोड़ रुपये से ज्यादा इक–ा किया और डीजल पर सात रुपये लीटर स्टेट की तरफ से वैट लगाया, लेकिन करोड़ों रुपये वहां से आने के बावजूद न तो प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं, न जनहित की योजनाएं चल रही हैं।

हिमाचल में दूसरे साल लगातार अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश

आकसा शिमला। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे साल अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बादल बरसे हैं। इस वर्ष एक से 30 अप्रैल तक सामान्य से पांच फीसदी अधिक बारिश हुई। वर्ष 2023 में अप्रैल के दौरान सामान्य से 63 फीसदी अधिक बारिश हुई थी। 2022 में सामान्य से 89 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई थी।

दस साल बाद शिमला में अधिकतम तापमान भी सबसे कम रिकॉर्ड हुआ। इस वर्ष अप्रैल के अधिकांश दिन ठंडे मौसम में ही बीते।

राजधानी में 26 अप्रैल को इस माह का सबसे अधिक 26.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। पहले के वर्षों में अप्रैल के दौरान पारा 28 डिग्री तक जाता था। प्रदेश के मैदानी जिला ऊना में भी इस बार अप्रैल में सिर्फ एक बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा।

बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में अधिकतम पारा 37 और 38 डिग्री तक ही रहा।

राजधानी शिमला सहित ऊंचाई वाले अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी ठंड से बचाव के लिए जैकेट और स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं। ठंड के कारण सर्दी–जुकाम और बुखार से पीड़ित दर्जनों मरीज रोजाना अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

ऊना में साल 2022 के दौरान अधि. कतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा था।

2023 में पारा 40 डिग्री को भी नहीं छू सका। इस बार सिर्फ एक बार 26 अप्रैल को ऊना का पारा 40 डिग्री पहुंचा।

राजधानी शिमला में अप्रैल के दौरान अधिकांश दिनों में अधिकतम तापमान औसतन 20 और 22 डिग्री के बीच ही रहा।

उधर, अप्रैल के दौरान प्रदेश में 67.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इस अवधि में 64 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है।

साल	कितने फीसदी बारिश
2004	– 25 प्रतिशत।
2005	– 78 प्रतिशत।
2006	– 61 प्रतिशत।
2007	– 86 प्रतिशत।
2008	– 27 प्रतिशत।
2009	– 22 प्रतिशत।
2010	–23 प्रतिशत।
2011	– 01 प्रतिशत।
2012	–23 प्रतिशत।
2013	–58 प्रतिशत।
2014	– 01 प्रतिशत।
2015	–34 प्रतिशत।
2016	– 20 प्रतिशत।
2017	–35 प्रतिशत।
2018	–11 प्रतिशत।
2019	–50 प्रतिशत।
2020	–12 प्रतिशत।
2021	–70 प्रतिशत।
2022	–89 प्रतिशत।
2023	–63 प्रतिशत।
2024	–67.3 प्रतिशत।

राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था - राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा, राहुल गांधी के बयान को बताया आपत्तिजनक

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है और कहा कि इस तरह के बयान समाज में भेदभाव पैदा करने वाले हो सकते हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आमंत्रित किया गया था। ये बयान आपत्तिजनक, असत्य और भ्रामक है।

बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात के गांधी नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इसलिए नहीं आमंत्रित किया गया था क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। ट्रस्ट ने इस बयान पर संज्ञान लिया और सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वीडियो संदेश देकर जवाब दिया है।

चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों के अलावा ऐसे गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया था जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में देश का सम्मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े मजदूरों व गरीबों को भी ट्रस्ट ने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। सभी ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजन भी किया। राहुल गांधी का ये बयान भ्रामक, असत्य और आपत्तिजनक है। भगवान श्रीराम ने कभी भी अपने जीवन में किसी से भी भेदभाव नहीं किया इसलिए ट्रस्ट किसी के साथ भी भेदभाव करने का विचार नहीं रख सकता है। ट्रस्ट में संत-महात्मा भी शामिल हैं जो कि समाज के हर व्यक्ति को भगवान का रूप मानकर काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान समाज में भेदभाव पैदा करने वाला सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम इस पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हैं। हम लोगों को जोडऩे का काम करते हैं।

दलित महिला से लिव इन रिलेशनशिप में जन्मी बेटी का स्कूल में होगा एडमिशन

भोपाल। लिव इन रिलेशनशिप में दलित महिला से जन्मी बेटी को स्कूल में एडमिशन नहीं देने के मामले में एससी आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने जबलपुर कलेक्टर को पत्र भेजकर कहा है कि सुनीता आर्या की बेटी का एडमिशन स्कूल में करवाकर उनके साथ किये गए जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताडऩा पर स्कूल के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन भेजें। आयोग ने यह कार्रवाई द मूकनायक की खबर को संज्ञान में लेकर की है, आयोग के पत्र में इसका उल्लेख भी किया गया है। द मूकनायक ने 9 अप्रेल 2024 को यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।

29 अप्रेल 2024 को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने इस संबंध में जबलपुर कलेक्टर को पत्र लिख कर कहा कि द मूकनायक न्यूज बेवसाइट में प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेकर अनुसूचित जाति वर्ग की एकल माँ सुनीता आर्या जैविक पिता मनीष जैन (सामान्य वर्ग) की पुत्री का एडमिशन जबलपुर के प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में करवाने एवं उनके साथ किये गये जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताडना पर स्कूल के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में । मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने इस संबंध में जबलपुर कलेक्टर को पत्र लिखा.

इधर, खबर सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग ने भी कार्रवाई शुरू की है। खबर के प्रका. शित होते ही सम्बंधित आयोगों ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर जांच प्रतिवेदन मांगा है। एससी आयोग ने लिखा की- द मूकनायक न्यूज बेवसाइट में प्रकाशित समाचार मध्यप्रदेश दलित महिला से लिव इन रिलेशनशिप में जन्मी बेटी को एडमिशन नहीं दे रहे स्कूल संबंधी शिकायत की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। .पया नियमानुसार प्रार्थिया की बेटी को स्कूल में प्रवेश दिलाने संबंधी उचित कार्यवाही कर प्रार्थिया की समस्या का समाधान कर जांच प्रतिवे. दन एक माह में आवश्यक रूप से आयोग को भिजवाने का कष्ट करें।

क्या था मामला?

दरअसल, साल 2010 में सुनीता आर्य की पहचान भोपाल में मनीष जैन से हुई थी।

सुनीता तलाकशुदा महिला थी। मनीष और सुनीता के बीच प्रेम हुआ, दोना. ने ही साथ रहने का फैसला किया। सुनीता 2014 में प्रेग्नेंट हो गईं, उन्होंने जैसे ही ये बात मनीष को बताई तब मनीष ने सुनीता को कहा कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा उनका नहीं है। और इतना कहकर मनीष सुनीता से अलग हो गया। जनवरी 2015 में सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद मनीष ने भोपाल जिला न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि सुनीता उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, जबकि यह बच्चा उनका नहीं है। सुनीता ने कोर्ट से डीएनए टेस्ट की मांग की और रिपोर्ट आने पर यह सामने आया कि बेटी सुनीता और मनीष की ही है।

डीएनए टेस्ट के बाद मामला मीडिया तक पहुँचा।

हरियाणा के गुरुग्राम से राज बब्बर कांग्रेस प्रत्याशी

चंडीगढ़। हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस हाईकमान ने अभिनेता व पंजाबी सुनार चेहरे राज बब्बर को प्रत्याशी बनाया है। यहां से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन तमाम गुना भाग के बाद हाईकमान ने सेलिब्रिटी चेहरे पर मुहर लगा दी। मंगलवार रात कांग्रेस पार्टी ने टिकट की घोषणा की। इससे पहले, 25 अप्रैल को कांग्रेस की ओर से प्रदेश की 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे। गुरुग्राम सीट पर पेंच फंसने के चलते इसे रोक लिया गया था।

रोक हटे भरूण की लिंग जांच से गर्भ में लड़की की जानक. ारी मिलेगी तो पैदा होने के बाद उसकी जान बचा सकते हैं

नई दिल्ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख आरवी अशोकन ने कहा है कि भ्रूण का लिंग पता करने पर रोक लगाने से कन्या भ्रूण हत्या तो रुक सकती है, लेकिन इससे बच्ची के पैदा होने के बाद उसकी हत्या नहीं रोकी जा सकती। ये बात अशोकन ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कही।

उन्होंने कहा कि मौजूदा प्री-कंसेप्शन और प्री-नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्नीक एक्ट में बदलाव के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। मौजूदा कानून भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए प्री-नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्नीक पर रोक लगाता है और ऐसा करने वाले डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराता है। इसमें हमारी तरफ से एक सुझाव ये है कि क्यों न भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाए और फिर कन्या भ्रूण की रक्षा की जाए।

सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए मेडिकल सॉल्यूशन पर निर्भर नहीं कर सकते

अशोकन ने कहा कि एक सामाजिक बुराई के लिए आप मेडिकल सॉल्यूशन पर निर्भर नहीं कर सकते। क्या हमारा सुझाव काम करेगा या क्या ये प्रैक्टिकल है? इस पर बहस कर सकते हैं। अगर आपने सामाजिक बुराई को ठीक नहीं किया तो कन्या भ्रूण हत्या तो रुक जाएगी, लेकिन पैदा होने के बाद बच्चियों को मारा जाना जारी रहेगा।

अशोकन ने कहा कि उनके नजरिए से,एक्ट को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ दिया गया है, ये सिर्फ मौजूदा स्थिति को देखता है। कन्या भ्रूण हत्या रो. कना हमारी भी प्राथमिकताओं में है, लेकिन हम इस एक्ट में बताए गए तरीके से सहमत नहीं हैं। इसकी वजह से डॉक्टरों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है।

सभी डॉक्टरों को गुनहगार और जीवन-रोधी मान लेना गलत

अगर मौजूदा व्यवस्था से एक कानून हटाया जा सके, तो हमएक्ट को हटाना चाहेंगे। इस कानून को इस व्यवस्था में जगह नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टरों की एसोसिएशन लंबे समय सेएक्ट पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही है।

गर्ल चाइल्ड को बचाने के मामले में हमारा नजरिया अलग नहीं है। हमारा भी यही मकसद है कि बच्ची की जान बचाई जानी चाहिए, लेकिन ये मान लेना गलत है कि सभी डॉक्टर्स गुनहगार और जीवन-विरोधी है।

फॉर्म न भरे जाने को कन्या भ्रूण हत्या के बराबर मानना ठीक नहीं

अशोकन ने कहा कि नियम कहते हैं कि मशीनों को एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं ले जाया जा सकता है। यहां तक कि फॉर्म न भरे जाने को कन्या भ्रूण हत्या के बराबर देखा जाता है।एक्ट के तहत फॉर्म स्न में प्रेग्नेंट महिला की मेडिकल हिस्ट्री और अल्ट्रासाउंड करने की वजह रिकॉर्ड की जाती है।

मौजूदा कानून के तहत जो डॉक्टर फॉर्म ठीक से नहीं भर रहे हैं, उन्हें वही सजा दी जा रही है जो भ्रूण की जांच करने पर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि अगर आप फॉर्म स्न नहीं भरते हैं, तो आप कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है।

कन्या भ्रूण को टैग करके मां पर नजर रखनी चाहिए

अशोकन ने कोयंबटूर से 15 दिन पुराना एक वाकया सुनाया, जब एक गायनेकोलॉजिस्ट को फॉर्म न भरने के चलते अपराधी घोषित कर तीन साल के लिए जेल भेज दिया गया। ये कानून ह्रत्रह्र पर आधारित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है। इसे आम आदमी के नजरिए से बनाया गया है।

अशोकन ने कहा कि इसलिए हम इसे लेकर चर्चाएं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों न भ्रूण का लिंग पता किया जाए, कन्या भ्रूण का पता लगाया जाए और फिर उस बच्ची को बचाया जाए। ये संभव है। कन्या भ्रूण को टैग कीजिए, देखिए कि उसे क्या होता है। मां पर नजर रखिए और देखिए कि बच्ची को नॉर्मल तरीके से डिलीवर किया जाए।

कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे मेडिकल प्रोफेशन को कठघरे में खड़ा किया गया

अशोकन ने कहा कि कुछ गलत लोगों की वजह से पूरा मेडिकल प्रोफेशन कठघरे में खड़ा कर दिया गया है, जो कि गलत है। मैं चाहता हूं कि प्रोफेशन को कठघरे से बाहर निकाला जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भ्रूण लिंग की जांच को अनुमति दी जानी चाहिए। अगर आप इसे मान सकते हैं, तो मान लीजिए।

अगर नहीं मान सकते हैं, तो उन पॉइंट्स को हटा दीजिए जिससे डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जाता है। जिस डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे हैं, वह ढ्ढरू्र की सेंट्रल वर्किंग कमेटी में डिस्कस किया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में चर्चा हो।

आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम का ढांचा खराब

अशोकन ने इस इंटरव्यू में आयुष्मान भारत स्कीम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य अनाथ है। कोरोना संकट से देश ने कोई सीख नही ली है। ऐसी महामारी के बाद भी कोई स्वास्थ्य पर बात नहीं करना चाहता है। राजनीतिक दलों के लिए हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि सभी लोग ऑल इज वेल जोन में हैं।

अशोकन ने कहा कि सरकार की लैगशिप योजना आयुष्मान स्कीम का विजन बहुत अच्छा था और इससे काफी उम्मीदें भी जुड़ी थीं। लेकिन स्कीम का ढांचा बेहद खराब है और इसमें फंड्स की इतनी भारी कमी है कि ये स्कीम कभी भी बंद पड़ सकती है।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस स्कीम को पीएम ने गरीब लोगा. ं के लिए शुरू किया था, लेकिन इसका ढांचा ब्यूरोक्रेट्स ने तैयार किया था। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जाने की जरूरत है।

प्रेसिडेंट बोले- रामदेव ने झूठ की हदें पार कीं -कोविड ठीक करने का दावा किया था, मॉडर्न मेडिसिन को बेकार और दिवालिया साइंस कहा

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरवी अशोकन ने कहा कि बाबा रामदेव ने उस समय सभी हदें पार कर दीं जब उन्होंने कोविड-19 ठीक करने का दावा किया।

उन्होंने कहा कि रामदेव ने मॉडर्न मेडिसिन को स्टुपिड और बैंकरप्ट साइंस यानी बेकार और दिवालिया विज्ञान भी कहा था। न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में अशोकन ने ये बातें कहीं।

अमृता वड़िंग सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुईं, एसजीपीसी ने की निंदा, मांगी माफी

चंडीगढ़/अमृतसर। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग ने एक चुनावी सभा में बीते रोज कांग्रेस पार्टी के चिह्न हाथ की तुलना गुरुओं के पंजे यानी हाथों से की। यहां तक कि अमृता वड़िंग ने चुनावी सभा में लोगों से इसे गुरुओं का पंजा कहकर कांग्रेस पार्टी को वोट देने को कहा। इसको लेकर सोमवार देर शाम से यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुआ।

जैसे ही यह वीडियो ट्रोल होने लगा, पंजाब के धार्मिक संगठनों, सिख समुदाय और लोगों ने अमृता वड़िंग के इस विवादित बयान का जमकर विरा. ध करना शुरू कर दिया। यहां तक कि एसजीपीसी ने मामले में संज्ञान लेते हुए अमृता वड़िंग के बयान की निंदा की। मंगलवार सुबह इससे पहले कोई नई राजनीतिक मुसीबत खड़ी होती, अमृता वड़िंग ने सोशल मीडिया पर आकर सार्वजनिक तौर पर अपने विवादित बयान के लिए माफी मांग ली।

अमृता ने कहा कि जाने-अनजाने में दिए गए बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। मेरी इस तरह की कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि इससे पहले इस बयान की निंदा हो रही थी। एसजीपीसी ने भी उनके बयान की निंदा की थी। साथ ही कहा था कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं, इस बयान को लेकर निर्वाचन आयोग में भी शिकायत की गई है। शिरोमणि अकाली दल द्वारा इस मामले में शिकायत की गई और कहा गया है कि अमृता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के चुनाव चिह्न श्पंजाज्य को श्री गुरु नानक देव जी का पंजा कहने पर कड़ा नोटिस लिया है।

अमृता वडिंग को फटकार लगाते हुए इस मुद्दे पर तुरंत सिख संगत से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद माफी मांगी गई है। ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि राजनीतिक नेता राजनीतिक हितों के लिए गुरु साहिब के नाम और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसे किसी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

चेतावनी आ सकती है प्रोस्टेट कैंसर की सुनामी, साल 2040 तक मृत्युदर में 85 प्रतिशत वृद्धि की आशंका

वैश्विक स्तर पर कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुरुषों में प्रोस्टेट और लंग्स कैंसर के मामले सबसे अधिक रिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल का जोखिम सबसे अधिक होता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कैंसर के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जा रही है। अध्ययनों में कहा जा रहा है कि जिस तरह से समय के साथ लोगों की लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है, तमाम प्रकार के हानिकारक रसायनों से मिश्रित आहार का हम सभी रोजाना सेवन कर रहे इसने कैंसर के खतरे को और भी बढ़ा दिया है। इसी से संबंधित एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बड़ी चेतावनी जारी की है।

द लैंसेट कमीशन ने तमाम अध्ययनों से जो निष्कर्ष निकाला उससे पता चलता है कि आने वाले वर्षों में प्रोस्टेट कैंसर एक बड़ा खतरा बनकर उभरने वाला है। अध्ययनकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जिस तरह के रुझान देखे जा रहे हैं इससे पता चलता है कि दुनिया में श्प्रोस्टेट कैंसर की सुनामीश आने वाली है, इस कैंसर के मामलों में अपरिहार्य वैश्विक वृद्धि को लेकर आशंका जताई गई है।

इससे न सिर्फ वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र पर बड़ा दबाव बढ़ेगा साथ ही कैंसर से मृत्युदर बढने को लेकर भी चिंता जताई गई है।

2040 तक दो गुना बढ़ सकते हैं मामले

अध्ययन की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने बताया कि साल 2040 तक दुनियाभर में प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने होकर 2.9 मिलियन (29 लाख) से अधिक हो सकते हैं। इसके अलावा मृत्यु के मामलों में भी 85त्न बढ़ोतरी की आशंका है जोकि लगभग सात लाख से अधिक मौतों का कारण बन सकती है।

पेरिस में मूत्र रोग विशेषज्ञों की एक बैठक में आयोग ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे उच्च आय वाले देशों में पहले से ही इस कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी रही है, हालांकि अब निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे बढने की आशंका है।

50 की आयु में भी हो सकता है खतरा

द लैंसेट रिपोर्ट के प्रमुख लेखक और लंदन में कैंसर अनुसंधान संस्थान में प्रोस्टेट और मूत्राशय कैंसर अनुसंधान के प्रोफेसर निक जेम्स ने कहा कि यह वृद्धि बड़े स्वास्थ्य संकट के तौर पर उभर रही है। उम्र बढने के साथ पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, इसके लिए कई और भी जोखिम कारक हैं। अब कम उम्र में भी प्रोस्टेट से संबंधित दिक्कतें देखी जा रही है जिसपर आमतौर पर शुरुआत में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जिसके बाद में गंभीर रूप लेने और कैंसर बनने का खतरा हो सकता है।

उच्च आय वाले देशों में कैंसर के मामलों में बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन अब हम आर्थिक रूप से कमजोर देशों में आने वाले दशकों में 50–60–70 साल के लोगों में भी इसके मामले बढ़ते हुए देख सकते हैं।

पीएसए स्क्रीनिंग को लेकर भी उठे सवाल

वैज्ञानिकों की टीम ने प्रोस्टेट–स्पेसिफिक एंटीजन (पीएसए) स्क्रीनिंग के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई है। न्यूयॉर्क शहर में मेमो. रियल स्लोअन केटरिंग कैंसर सेंटर में डॉक्टर एंड्रयू विकर्स कहते हैं, हमने पाया कि मरीजों को पीएसए के बारे में स्वयं निर्णय लेने की सर्वव्यापी नीति सही नहीं है। पीएसए स्क्रीनिंग को लेकर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

इस परीक्षण को लेकर पहले से ही बहुत विवाद रहा है। डॉक्टर्स मानते रहे हैं कि पीएसए परीक्षण अचूक नहीं हैं। यह संभव है कि जब कैंसर मौजूद न हो तो आपके पीएसए का स्तर बढ़ा हुआ हो, और जब कैंसर मौजूद हो तो यह उस स्तर पर न दिखे।

विशेषज्ञों ने कहा–सभी लोग करें बचाव के उपाय

अध्ययनकर्ताओं ने कहा, प्रोस्टेट कैंसर को लेकर जो जोखिम देखा जा रहा है वह बड़ा चिंताकारक है। इसको लेकर सभी पुरुषों को विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। प्रोस्टेट कैंसर की रोकथाम के लिए कोई विशिष्ट तरीका तो नहीं है लेकिन आप व्यायाम और स्वस्थ आहार जैसे विकल्पों को चुनकर इसके खतरे को कम कर सकते हैं।

कुछ अध्ययनों में, नियमित रूप से हाई फैट वाले खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से पशुओं पर आधारित वसा के सेवन को प्रोस्टेट कैंसर के लिए बड़ा जोखिम कारक माना जाता रहा है। आहार में फैट वाली चीजों की मात्रा कम रखने की सलाह दी जाती है। नियमित व्यायाम को भी प्रोस्टेट कैंसर के लिए जोखिमों को कम करने वाला पाया गया है।

सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट कौन सा आपके लिए फायदेमंद?

स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ और पौष्टिक आहार के सेवन पर जोर दिया जाता रहा है। आमतौर पर माना जाता रहा है कि वजन को कंट्रोल रखने, ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्याओं के जोखिमों को कम करने के लिए आहार में फैट वाली चीजों की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि बेहतर सेहत के लिए आपको आहार के माध्यम से कुछ प्रकार के फैट्स की भी आवश्यकता होती है। जिन दो फैट्स की सबसे ज्यादा चर्चा रही है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट उनमें से एक है। अध्ययनों में माना जाता रहा है कि अनसैचुरेटेड फैट अधिक फायदेमंद होते हैं और इससे सेहत को कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। वहीं सैचुरेटेड फैट की मात्रा शरीर के लिए कई प्रकार से हानिकारक दुष्प्रभावों वाली हो सकती है।

सैचुरेटेड फैट से रक्त वाहिकाओं को नुकसान

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, सैचुरेटेड फैट का अधिक सेवन रक्त वाहिकाओं में वसा के जमाव का कारण बन सकते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों के सख्त होने) का जोखिम हो सकता है। इसके विपरीत, असंतृप्त वसा वाली चीजों को धमनियों को स्वस्थ रखने के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है।

अनसैचुरेटेड फैट वाली चीजें मुख्यरूप से पौधों के स्रोतों (जैसे ऑलिव, एवोकाडो और नट्स) से प्राप्त होते हैं, जबकि अधिकांश मात्रा में संतृप्त वसा पशुओं के स्रोतों (जैसे रेड मीट, पोल्ट्री) से मिलता है।

आहार में कम रखें सैचुरेटेड फैट

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) के विशेषज्ञों के अनुसार, संतृप्त वसा की मात्रा आपके दैनिक कैलोरी सेवन का 6त्न से कम होना चाहिए। डाइट में सैचुरेटेड फैट वाली चीजों के सेवन को सीमित करना आपके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक हो सकता है।

अध्ययनों में पाया गया है कि अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट वाली चीजों का सेवन एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकती है जिससे हार्ट की समस्याओं के बढने का खतरा रहता है।

इन चीजों का कम कर दें सेवन

आहार में सैचुरेटेड फैट वाली चीजों की मात्रा कम रखने के लिए पशुओं पर आधारित चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। विशेषतौर पर रेड मीट वाली चीजें, मक्खन, आइसक्रीम और तली हुई चीजों की मात्रा आहार में कम रखकर आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा आहार से संबंधित कुछ सुझावों को ध्यान में रखकर भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम रखने और शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद मिल सकती है।

स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए आहार में कैलोरी की मात्रा को संतु. लित करें।

साबुत अनाज, लीन और पौधों पर आधारित प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के फल–सब्जियां खाएं।

नमक, चीनी, मांस, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और शराब का सेवन कम से कम करें।

हीटवेव से करोड़ों बच्चों की जान को खतरा लिवर डैमेज के जोखिमों को लेकर भी अलर्ट

पर्यावरणीय परिवर्तन और साल–दर साल बढ़ते तापमान को सेहत के लिए बहुत हानिकारक माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने हालिया रिपोर्ट में बढ़ते हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी कर कहा है कि दुनिया के कई देशों में हीटवेव जानलेवा दुष्प्रभावों का कारण बन सकती है। बच्चों की सेहत पर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। इतना ही नहीं ईस्ट एशिया और प्रशांत के देशों में बढ़ती गर्मी के कारण करोड़ों बच्चों की जान पर संकट बना हुआ है। यह दुनिया के वो हिस्से हैं जहां हीटवेव और बढ़ती गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बनी रहती है और समय के साथ ये बढ़ती भी जाती है। इतना ही नहीं विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2024 सबसे गर्म वर्ष भी हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एशियाई देशों, विशेषतौर पर भारत में भी बढ़ती गर्मी को लेकर सभी लोगों को सावधानी बरतते रहने की सलाह दी है।

भारत में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है तापमान

भारत में पिछले एक महीने में तेजी से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों को कैसे नियंत्रित किया जाए इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों के साथ एक बैठक कर रणनीति निर्धारित की है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, गर्मी के संपर्क में आने से कई प्रकार के अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। इससे हर साल लोगों में फैंटनेस, हीट स्ट्रोक, त्वचा की समस्या और ब्लड प्रेशर के जोखिमों के बढने का भी खतरा रहता है। हीट स्ट्रोक की स्थिति में हमारा शरीर तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता खो देता है जिसके कई गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी हो सकते हैं।

हीटवेव से लिवर की बढ़ सकती हैं दिक्कतें

कुछ अध्ययनों में अलर्ट किया जाता रहा है कि हीटवेव या गर्मी के अधिक संपर्क में रहने की स्थिति किडनी और लिवर जैसे अति महत्वपूर्ण अंगों को भी गंभीर क्षति पहुंचाती हुई देखी जा रही है। गंभीर स्थितियों में इसके कारण लिवर इंजरी और लिवर फेलियर तक का जोखिम बढ़ जाता है।

विशेषज्ञों ने बताया, हीटवेव का सबसे ज्यादा शिकार युवा आबादी को देखा जा रहा है। कुछ लोगों में हीटवेव के कारण किडनी इंजरी, लैक्टिक एसिडोसिस (रक्तप्रवाह में लैक्टिक एसिड का निर्माण), थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (ब्लड में प्लेटलेट काउंट काफी कम होना) और रबडोमायोलिसिस (मांसपे. शियों के टिशू के ब्रेकडाउन से रिलीज होने वाले हानिकारक प्रोटीन) जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ?

लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन बताते हैं, हीटस्ट्रोक के कारण लिवर इंजरी के मामले देखे जाते रहे हैं हालांकि ये काफी दुर्लभ हैं। आमतौर पर शुरुआत में इसका सही तरीके से निदान भी नहीं हो पाता है। हालांकि यदि रोगी को गंभीर हाइपोथर्मिया (तापमान 102 डिग्री से अधिक होने) है तो कुछ स्थितियों में ये गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का कारण बन सकती है। हीटवेव की स्थिति के कारण क्रिएटिनिन बढने, पेशाब का उत्पादन कम होने और अति गंभीर स्थिति में मल्टी ऑर्गन फेलियर की भी समस्या हो सकती है।

डॉ बताते हैं, लिवर कोशिकाओं में रक्त का संचार बाधित हो जाने की स्थिति में लिवर से संबंधित गंभीर समस्याओं का खतरा रहता है।

डॉक्टर्स कहते हैं, समय के साथ बढ़ती गर्मी और शरीर पर होने वाले इसके दुष्प्रभावों से बचाव के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है। शरीर के तापमान को बढने से रो. कने के उपाय किए जाने चाहिए।

विटामिन–डी के लिए आवश्यक है सूर्य की रोशनी तो क्या गर्मियों में भी धूप में रहना जरूरी?

विटामिन–डी की हमारे शरीर को नियमित रूप से जरूरत होती है। ये न सिर्फ हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक माना जाता है, साथ ही कोशिकाओं को स्वस्थ रखने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी विटामिन–डी जरूरी है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहना शरीर के लिए विटामिन–डी की जरूरतों को पूरा करने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। हालांकि गर्मी के दिना. ं में जब सूर्य की तेज काफी बढ़ जाती है, ऐसे में भी क्या हमें सूर्य के संपर्क में रहने की जरूरत होती है?

अध्ययनकर्ताओं ने बताया, सूर्य की रोशनी से न सिर्फ हमें विटामिन–डी प्राप्त होता है साथ ही ये हमारे मान. सिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी जरूरी माना जाता है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहने से ब्रेन में हैपी हार्मोन सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। तो क्या अप्रैल–मई के महीने में भी हमारे लिए धूप में समय बिताना जरूरी है?

विटामिन–डी और सूर्य की रोशनी

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जब भी आप सूर्य के बारे में सोचते हैं, तो पहला विचार इससे त्वचा को होने वाले नुकसान के बारे में आता है। कई अध्ययनों में भी कहा जाता रहा है कि सूर्य के अधिक संपर्क में रहने के कारण त्वचा कोशिकाओं की क्षति और यहां तक कि कैंसर का भी जोखिम हो सकता है। विटामिन–डी की हमें निरंतर आवश्यकता होती है इसलिए सूर्य की रोशनी भी जरूरी है। पर गर्मी के दिनों में इसको लेकर कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है।

सुबह के समय सूर्य की रोशनी लेना लाभकारी

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, गर्मी के दिनों में विटामिन–डी की पूर्ति के लिए भी सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहना जरूरी है। इसके लिए सुबह के समय की रोशनी को सबसे फायदेमंद माना जाता है। मार्निंग वॉक के समय में 5–10 मिनट सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहकर इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

हालांकि दिन के समय में धूप में जाने के कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, इसलिए गर्मियों में सुबह के समय धूप लेना पर्याप्त माना जा सकता है।

नोट- आप का सामना की हेल्थ,युवा, शिक्षा सामना कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से पेशेवर पत्रकारों द्वारा बातचीत के आधार पर पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किये जाते है। आप का सामना लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी,शिक्षा,जॉब के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर,शिक्षक से परामर्श लें।

इस पूरी दुनिया में गरीब वही है, जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना।
-डॉ० भीमराव अंबेडकर

संपादकीय

ईरान बन सकता था पश्चिम एशिया की ताकत

ईरान ने हाल ही मं इजरायल पर ड्रोन अटैक करके पश्चिम एशिया में खतरा बढ़ा दिया है। इससे ईरान की छवि और खराब हो गई है। जो देश पश्चिम एशिया की एक ताकत बन सकता था, वो विदेश हस्तक्षेप के और इस्लामिक कट्टरपंथ के चक्कर में बर्बाद हो गया।

ईरान पश्चिम एशिया की एक आधुनिक ताकत बन सकता था। लेकिन विद. शी दखल (बाहरी हस्तक्षेप) और धर्मगुरुओं (आयतोल्लाह) ने इसे बर्बाद कर दिया। हाल ही में, इजरायल पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की हमले ने ईरान को दोबारा पश्चिम एशिया में एक बड़े खतरे के रूप में पेश किया। ईरान को शांति के खिलाफ रहने वाला देश माना जाने लगा है। ईरान ने हिज़बुल्लाह से लेकर हूती विद्रोहियों तक कई क्षेत्रीय गुटों को खड़ा किया है, जो उसके रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करते हैं। देश के अंदर मुस्लिम धर्मगुरु सख्त नियंत्रण रखते हैं और कट्टरपंथी इस्लाम को थोपते हैं और ईरानी महिलाओं की आजादी छीन लेते हैं। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। ईरान एक महान आधुनिक ताकत बन सकता था।

ईरान में कब आया बड़ बदलाव

ईरान के लिए एक बड़ा बदलाव 1953 में आया, जब लोकतांत्रिक रूप से चुने गए ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देघ के खिलाफ तख्तापलट हुआ। सीआईए समर्थित इस तख्तापलट ने ईरान की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को भारी चोट पहुंचाई। मोसद्देघ ने ईरान को वास्तविक अधिकार–आधारित लोकतंत्र में बदलने के उद्देश्य से कई सुधार किए थे। इस तख्तापलट ने शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के हाथों में सत्ता केंद्रित कर दी, जिसने एक क्रूर शासन बनाया और 1979 में धर्मगुरुओं की इस्लामी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।

40 साल से लगी हैं पाबंदियां

ईरान पर 40 साल से पश्चिमी देशों की पाबंदियां लगी हुई हैं। इससे ईरानी अर्थव्यवस्था का विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है। ईरान की मजबूती इस बात से पता चलती है कि वे खुद के ड्रोन और मिसाइल बनाते हैं, उनका परमाणु प्रोग्राम गुप्त रूप से चल रहा है और वो अभी भी तेल का निर्यात कर रहे हैं।

पढ़ी लिखी आबादी वाला देश

ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है और शिक्षा के स्तर में वो पश्चिम एशिया में सबसे ऊपर है। वहां 70 प्रतिशत विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के स्नातक महिलाएं हैं! सोचिए अगर ईरान को पाबंदियों से मुक्ति मिल जाए तो इन प्रतिभाओं का क्या योगदान हो सकता है।

परमाणु समझौते से ईरान को एक सामान्य देश बनने की उम्मीद जगी थी। लेकिन ट्रम्प ने उस समझौते को खत्म कर दिया और बाइडन ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। इससे ईरान विरोधी धर्मगुरु खुश हो गए, इजरायल और सऊदी अरब खुश हो गए। लेकिन आम ईरानी निराश हो गए, जिन्हें लगता है वो इस्लामिक देश में फंसे हुए हैं। उनके बेहतर जीवन का दरवाजा फिर से बंद हो गया। ईरान की स्थिति वैसी ही विद्रोही और अछूत देश की बनी हुई है।

युद्ध फैलने का खतरा

ईरान की ओर से इजरायल पर हमलों ने गाजा में युद्ध को और भी भयावह बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई बढने से लाल सागर रूट प्रभावित हो सकती है। दुनिया पहले से ही दो बड़े युद्ध के संकट को झेल रही है।

ईरान की ओर से इजरायल पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने छह महीने से गाजा में जारी इजरायल–हमास युद्ध के और फैलने का गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। पहले ही दो युद्धों के प्रभावों से बेहाल दुनिया के लिए अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि इजरायल इस हमले के जवाब में क्या और कैसा कदम उठाता है।

ईरान का बदला हालांकि ईरान ने अपने कदम को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताते हुए कहा है कि यह दमिश्क में उसके दूतावास पर हुए हमले का जवाब है। ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि इस कार्रवाई के बाद उसकी तरफ से मामले को खत्म माना जा सकता है, लेकिन अगर इजरायल ने फिर कोई गलती की तो नतीजे इससे भी गंभीर होंगे।

इजरायली रुख हमले से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपना यह सिद्धांत घोषित किया था कि श्जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे हम नुकसान पहुंचाएंगे।य वैसे भी ईरान की प्रतिक्रिया को अपेक्षा से ज्यादा सख्त माना जा रहा है। ऐसे में इजरायल अपनी जमीन पर सीधे हमले की ईरानी कार्रवाई को चुपचाप स्वीकार कर लेगा, इसके आसार नहीं दिखते।

अमेरिका की प्रतिक्रिया लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए जरा सी असावधानी दुनिया को बहुत बड़े संकट में धकेल सकती है। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायल की आत्मरक्षा के सवाल पर हर तरह के सहयोग का वादा करते हुए भी यह साफ कर दिया है कि उसकी ओर से की जाने वाली किसी आक्रामक कार्रवाई में वह साथ नहीं देंगे।

भारत की दुविधा भारत के लिए यह स्थिति खास तौर पर असमंजस पैदा करने वाली है। इजरायल और ईरान दोनों से ही उसके बहुत अच्छे और करीबी रिश्ते रहे हैं। मिसाइल हमले से एक दिन पहले ईरान ने होरमुज जलडमरूमध्य में इजरायल से जुड़े जिस कार्गो शिप पर कब्जा किया, उसमें 17 भारतीय नागरिक भी हैं। इसलिए भारत की पहली चुनौती इन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें छुड़ाने की बन गई है।

साइड इफेक्ट मगर जिस तरह के तनावपूर्ण हालात इजरायल और ईरान के बीच बन गए हैं, उसके साइड इफेक्ट भी कम गंभीर नहीं होने वाले। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पहले ही 90 डॉलर पार कर चुकी है। यह 100 डॉलर से ऊपर पहुंच सकती है। इसका सीधा प्रभाव महंगाई पर दिखेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन भी इससे प्रभावित होगी। लाल सागर रूट पहले ही हूती विद्रोहियों की कार्रवाई के चलते बाधित है।

संतुलित नजरिया

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जलवायु परिवर्तव और पारिस्थितिकी को लेकर एक संतुलन फैसला सुनाया है। अदालत ने दुर्लभ प्रजाति के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

राजस्थान और गुजरात में अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (सोहन चिडिया़) के लिए खतरनाक माने गए सोलर एनर्जी प्रॉजेक्ट से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो संतुलित रुख अपनाया है, वह पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास को लेकर जुडिशरी की नई सोच का संकेत करता है। पहली बार इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी के असंत. ुलन को संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से जोड़ा है।

रोक से दिक्कत रू मामला 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के प्रॉजेक्ट से जुड़ा है, जिस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में रोक लगा दी थी। उस समय कोर्ट के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि बिजली के इन तारों से टकराकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत होती है। राजस्थान और गुजरात का वह इलाका इन पक्षियों के आवागमन की राह में पड़ता है। मगर यही इलाका सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं से भरपूर भी माना जाता है। इस प्रॉजेक्ट पर रोक के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी देश की योजनाएं बुरी तरह बाधित हो रही थीं।

बीच की राह ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि इस तरह की एकतरफा रोक से बात नहीं बनती। पक्षियों को बचाना अगर महत्वपूर्ण है तो वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने का देश का संकल्प पूरा होना भी जरूरी है। लिहाजा, कोर्ट ने नए आदेश में 13000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इन पक्षियों के आवास के रूप में संरक्षित रखने और 77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन पर लगी रोक हटाने की बात कही।

संवैधानिक मूल्यों का संदर्भ रू जलवायु बदलाव के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए सरकार अपनी नीतियों में जो भी बदलाव ला रही हो, हालात की गंभीरता के मद्देनजर यह काफी नहीं माना जा रहा।

इन प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए इन्हें संवैधानिक मूल्यों से जोडने की जरूरत थी। जलवायु परिवर्तन से आम लोगों के जीवन पर पड़ते विप. रीत प्रभावों और ऊर्जा की कमी जैसे संकटों को नागरिकों के जीवन व समानता के अधिकारों से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश की है।

वैकल्पिक ऊर्जा : अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा की डिमांड में होने वाले कुल इजाफे का 25 प्रतिशत भारत में होगा।

पर्यावरण प्रदूषण का दबाव स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत बढ़ाएगा। भारत में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावना भी है।

इसे देखते हुए ही भारत सरकार ने 2030 तक 500 गिगावॉट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने और 2070 तक शून्य उत्सर्जन की स्थिति में पहुंचने का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में इन सभी तथ्यों का ध्यान रखा गया है।

बेहतर भविष्य की ओर रू कुल मिलाकर शीर्ष अदालत का यह फैसला ऐसा कानूनी नजरिया देता है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाए रखते हुए विकास सुनिश्चित करने की राह पर आगे बढना़ आसान बनाएगा।

भीड़ की अराजकता

पश्चिम बंगाल में अधिकारियों पर हुए भीड़ हमले में चुनावी माहौल में जांच की मांग की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत है ताकि विश्वसनीयता बनी रहे।

पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर इलाके में अधिकारियों पर हुआ भीड़ का हमला बताता है कि हमारे प्रशास. निक और राजनीतिक तंत्र ने पिछले अनुभव से कोई सबक नहीं लिया है। इस घटना ने इसी जनवरी में हुए संद. `शखाली प्रकरण की याद ताजा कर दी है, जिसमें भीड़ ने (प्रवर्तन निद. `शालय) की टीम को निशाना बनाया था। एक बार फिर दोनों पक्षों की ओर से राजनीतिक बयानबाजी का सिल. सिला शुरू हो गया है, जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की संभावना को धूमिल बनाता है।

हाईकोर्ट का निर्देश – ऐसे में यह ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राजनी. तिक बयानों से हटकर पहले इस मामले से जुड़े ठोस तथ्यों पर गौर कर लिया जाए। पहली बात, इस मामले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है। दूसरी बात, मामला एक बम ब्लास्ट से जुड़ा है, जो दिसंबर 2022 में हुआ था। तीसरी, घटना भले दो साल पहले की हो, चौथी, इन आरो. पियों को पहले भी समन किया गया था, जिसे इन लोगों ने अनदेखा कर दिया था। पांचवीं और आखिरी बात यह कि टीम उपयुक्त वारंट के साथ गई थी।

संदेशखाली का अनुभव : किसी राज्य में सेंट्रल एजेंसी से जुड़े अधिकारियों के कामकाज में इस तरह बाधा डाला जाना बेहद खतरनाक और नुकसानद. `ह है। संदेशखाली वाले मामले में भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि बाद में मुख्य अभियुक्त गिरतार हुआ जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय दबंग नेता माना जाता था। पार्टी ने उसे निलंबित भी कर दिया। लेकिन उस घटना ने प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। हैरत की बात है कि पिछले अनुभव के बावजूद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी परोक्ष रूप सेकार्रवाई पर ही सवाल उठाया है। तृणमूल से जुड़े कई अन्य नेताओं ने भी आरोप लगाया है उनका कहना है कि इस तरह से रात में टीम भेजकर आरोपियों को पकडने का मकसद यही है।

इस खास मामले में प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी न की जाए तो भी यह साफ है कि चुनावी माहौल में अगर जांच एजेंसियां किसी एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आती हैं तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने के आसार होते हैं।

कानूनी प्रक्रिया का पालन : ऐसे में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कानून की तय प्रक्रिया का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। कारण यह है कि चुनावी माहौल में उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने से न केवल उनकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि देश में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी आंच आने का डर रहता है।

ओल्ड पेंशन स्कीम पर बदला रुख?

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जातिगत जनगणना, विकास दर, ओल्ड पेंशन स्कीम, विवादित मुद्दे, नीतियों की वैकल्पिक दिशा, चयन की स्वतंत्रता और वोटरों को कैसे आश्वस्त कर पाती है पर ध्यान केंद्रित किया।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणापत्र जारी कर उन प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट किया, जहां उसके मुताबिक सत्ता पक्ष का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है और अगर मतदाताओं ने मौका दिया तो सत्ता में आने पर वह उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। इस लिहाज से कांग्रेस के इस न्याय पत्र की कुछ बातें खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं।

कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना इस घोषणापत्र का अहम हिस्सा है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी परीक्षा होनी है। माना जा सकता है कि अगर इस बार की वोटिंग में इस मुद्दे की खास भूमिका नहीं दिखती है तो बहुत संभव है कि आने वाले दौर में आरक्षण जैसे मुद्दे की राजनीतिक अहमियत कम होती नजर आए।

विकास का दावा घोषणापत्र में कहा गया है कि 10 वर्षों का ह्रष्ठ शासन 10 साल के राज के मुकाबले विकास दर की कसौटी पर कमजोर साबित हुआ है। यह केंद्र की भाजपा सरकार के डिवेलपमेंट के नैरेटिव को चुनौती है। इन परस्पर विरोधी दावों की प्रामाणिकता के सवाल में उलझे बगैर यह देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि मतदाता किसके दावे पर अपनी मुहर लगाते हैं। हालांकि, कुछ समय पहले हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही ओर से लोकलुभावन वादे हुए थे। तब अधिक लोगों का झुकाव केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी की ओर दिखा।कल्याणकारी घोषणाओं पर जोर देने के बावजूद कांग्रेस का यह घोषणापत्र ओल्ड पेंशन स्कीम पर चुप्पी साधे हुए है। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का इस पर जोर था। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मिली कामयाबी के पीछे इस वादे की भी भूमिका बताई गई थी। लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों की राय थी कि यह वित्तीय समझदारी के खिलाफ है। ऐसे में कांग्रेस ने अगर सोच–समझे ढंग से इस मुद्दे पर कदम पीछे खींचने का जोखिम उठाया है तो इसकी सराहना होनी चाहिए।

विवादित मुद्दे सत्तारूढ़ भाजपा की नीतियों से खुद को अलग दिखाने के प्रयास में पार्टी ने उन विवादित मुद्दा. ं से भी परहेज नहीं किया है, जो खास तौर पर हाल के वर्षों में राजनीतिक और चुनावी लिहाज से हानिकारक करार दिए जाने लगे हैं। उदाहरण के लिए पार्टी ने खानपान, वेशभूषा, भाषा और पर्सनल लॉ के मामले में अल्पसंख्यकों समेत सभी नागरिकों के लिए चयन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात खास तौर पर कही है। वैकल्पिक दिशा कुल मिलाकर, मुख्य विपक्षी दल के इस घोषणापत्र को इस मामले में साहसिक कहा जाएगा कि इसने नीतियों की वैकल्पिक दिशा स्पष्ट करने की कोशिश की है।

सीबीआई की चार्जशीट में ये बातें आईं सामने मणिपुर में कुकी महिलाओं के नग्न परेड मामले में

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक आरोप पत्र के अनुसार, मणिपुर के थौबल जिले में भीड़ द्वारा कुकी–ज़ोमी समुदाय की दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीडऩ करने से ठीक पहले, दोनों सड़क के किनारे खड़ी पुलिस जिप्सी के अंदर बैठने में कामयाब रहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस से गाड़ी स्टार्ट करने का के लिए कहा तो पुलिस चालक ने उन्हें बताया कि कुंजी नहीं।

पुलिस जिप्सी में दो अन्य पीड़ित पुरुष भी बैठे थे. आरोपपत्र में कहा गया है कि तब मौजूद सभी पुलिसकर्मी मौके से चले गए क्योंकि एक बड़ी भीड़ ने पीड़ितों को वाहन के अंदर से बाहर निकाला।

सीबीआई जांच में पता चला कि 3 मई को चुराचांदपुर में हिंसक घटना हुई थी. अक्टूबर में गुवाहाटी की एक विशेष अदालत के समक्ष छह लोगों और एक किशोर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

डीजीपी (मणिपुर) राजीव सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बताया कि, पुलिस कर्मियों के खिलाफ पहले ही विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है. जब उनसे उनके खिलाफ किसी आपराधिक कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है।

एक वीडियो, जो जुलाई 2023 में वायरल हो गया था, और जिसने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था, उसमें दो महिलाओं – एक की उम्र 20 साल और दूसरी की 40 साल थी – को पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न अवस्था में एक खेत की ओर ले जाते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो ने वैश्विक स्तर पर मणिपुर की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।

सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा, इसके बाद अन्य स्थानों पर भी कई घटनाएं हुईं। मैतेई समुदाय की भीड़ ने घरों में आग लगाकर एक गांव पर हमला शुरू कर दिया और पड़ोसी गांवों में कुछ घरों को भी निशाना बनाया। भीड़ ने जानबूझकर चर्च में आग लगा दी. जांच में यह भी पता चला कि 4 मई को आसपास के मैतेई गांवों के प्रधानों और अन्य सामुदायिक गांवों के प्रमुखों की एक बैठक हुई थी. हालाँकि, बैठक में लिए गए निर्णय के बावजूद, भीड़ ने चर्च, कुछ घरों और आस–पास के गाँवों को जला दिया।

जांच से पता चला है कि डर के कारण, शिकायतकर्ता, तीन पीड़ित और दो पुरुष, एक अन्य व्यक्ति अपनी बेटी और एक पोती के साथ जंगल में भाग गए। भीड़ की नजर एक परिवार के सदस्यों के छिपने की जगह पर पड़ी और उन्हें देखते ही भीड़ से चिल्लाने की आवाज आई यहां लोग छुपे हुए हैं. भीड़ के सदस्य हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी लेकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें धमकाते हुए कहा, जिस तरह चुराचांदपुर में तुम लोगों ने हमारे (मैतेई लोगों) साथ व्यवहार किया, हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे।

भीड़ जबरदस्ती परिवार के सभी सदस्यों को मुख्य सड़क पर ले आई और उन्हें अलग कर दिया, भीड़ एक पीड़िता और उसकी पोती को एक दिशा में ले गई। दो महिलाएं और उनके पिता और उनके ग्राम प्रधान एक दिशा में, जबकि दो महिलाएं और दो पुरुष दूसरी दिशा में, सीबीआई ने कहा।

सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है कि भीड़ में से कुछ लोगों ने पीड़ितों को पास में एक गांव की सड़क के किनारे खड़ी पुलिस जिप्सी के पास जाने के लिए कहा।

पुलिस जिप्सी के पास आते समय, भीड़ ने फिर से पीड़ितों को अलग कर दिया... दो (महिला) पीड़ित पुलिस जिप्सी के अंदर जाने में कामयाब रहीं। पुलिस जिप्सी के अंदर सादी खाकी वर्दी पहने ड्राइवर समेत दो पुलिसकर्मी उनके साथ थे और तीन से चार पुलिसकर्मी बाहर थे। एक पीड़ित पुरुष ने पुलिसकर्मियों से वाहन चलाने का अनुरोध किया, हालांकि पुलिस जिप्सी के चालक ने जवाब दिया, कोई चाबी नहीं है।

वे बार–बार पुलिसकर्मियों से उनकी मदद करने और भीड़ द्वारा हमला किए जा रहे एक व्यक्ति को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा।

जिप्सी के चालक ने अचानक गाड़ी चलाई और लगभग 1,000 लोगों की हिंसक भीड़ के पास वाहन रोक दिया, और पीड़ित पुरुष ने फिर से पुलिस से गाड़ी स्टार्ट करने का अनुरोध किया, लेकिन उसे चुप रहने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद एक पुलिस कर्मी आया और उसने अपने साथियों को बताया कि उस व्यक्ति की सांसें थम गई हैं।

यह सुनने पर, पुरुष पीड़ित ने महिला पीड़ित को बताया कि उसके पिता को पीट–पीटकर मार डाला गया था, सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा।

सीबीआई जांच में पता चला कि एक बड़ी भीड़ पुलिस जिप्सी की ओर लौटी और गाड़ी को हिलाया।

उन्होंने जिप्सी के अंदर से एक पुरुष पीड़ित और दो महिला पीड़ितों को बाहर निकाला।

इस बीच, पुलिसकर्मी पीड़ितों को भीड़ के साथ अकेला छोड़कर मौके से चले गए। उन्होंने दोनों पीड़ित महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए और एक पुरुष पीड़ित की पिटाई शुरू कर दी पीड़ितों में से एक महिला पास के स्थान पर मौजूद थी और उसने पूरी घटना देखी, सीबीआई ने कहा।

मणिपुर सरकार के अनुरोध और केंद्र की अधिसूचना के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सामूहिक बलात्कार, हत्या, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल हैं।

इनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है हुइरेम हेरोदाश मैतेई (32), जिसे मणिपुर पुलिस ने 20 जुलाई को गिरतार किया था, अरुण खुंडोंगबम उर्फ नानाओ (31) को मणिपुर पुलिस ने 21 जुलाई को गिरतार किया था, निंगोम्बम तोम्बा सिंह उर्फ टोमथिन (18) को मणिपुर पुलिस ने 20 जुलाई को गिरतार किया था, पुखरीहोंगबाम सुरंजॉय मेइतेई (24) को मणिपुर पुलिस ने 22 जुलाई को गिरतार किया, नामीराकपम किरम मेइतेई (30) को मणिपुर पुलिस ने 24 जुलाई को गिरतार किया और एक किशोर को मणिपुर पुलिस ने 20 जुलाई को पकड़ा, आरोपपत्र में कहा गया है।

अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते किया युद्धविराम तो चली जाएगी सरकार, बेंजामिन नेतन्याहू की बढ़ीं मुश्किलें

तेल अवीव। गाजा युद्ध को कई महीने बीत चुके हैं और अभी तक हमास की कैद से सभी बंधक रिहा नहीं हो सके हैं। अब इस्राइल राफा पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल नेतन्याहू पर युद्ध रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। वहीं नेतन्याहू की सहयोगी पार्टियों ने चेतावनी दी है कि अगर राफा पर हमला रोका गया तो वे नेतन्याहू सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे और उस स्थिति में नेतन्याहू सरकार का गिरना तय हो जाएगा।

युद्धविराम की चल रहीं कोशिशें

युद्धविराम के लिए हमास के प्रतिनिधि सोमवार को मिस्त्र की राजधानी काहिरा पहुंच गए और मध्यस्थों द्वारा कोशिश की जा रही है कि इस्राइल और हमास के बीच युद्धविराम की बातचीत जल्द शुरू हो जाए। वहीं इस्राइली सेना राफा शहर पर हमले के लिए तैयार है। मिस्त्र सीमा पर स्थित राफा शहर में बड़ी संख्या में गाजा शरणार्थी ठहरे हुए हैं और अगर इस्राइली सेना राफा पर हमला करती है तो उसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने की आशंका है। अमेरिका भी इस्राइल पर युद्धविराम का दबाव बना रहा है।

वहीं इस्राइल का दावा है कि हमास की चार बटालियन राफा शहर में ही मौजूद हैं। ऐसे में इस्राइल हमले से पीछे हटने को तैयार नहीं है।

बेंजामिन नेतन्याहू की गिर सकती है सरकार

एक तरफ नेतन्याहू पर युद्धविराम के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है। वहीं घरेलू मोर्चे पर भी नेतन्याहू को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सरकार की सहयोगी दक्षिणपंथी पार्टी के नेता और इस्राइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने पीएम नेतन्याहू से अपील की है कि वे पीछ न हटें और राफा में जमीनी हमला करें।

स्मोट्रिच का कहना है कि युद्धविराम, इस्राइल की हार होगी। अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू को सरकार में रहने का हक नहीं होगा। वहीं मध्यमार्गी नेता सरकार से अपील कर रहे हैं कि बंधकों की रिहाई ज्यादा जरूरी है। ऐसे में बंधकों की रिहाई के लिए युद्धविराम होना चाहिए।

इस्राइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। दरअसल हमास के हमले के बाद से हजारों इस्राइली नागरिक अभी भी विस्थापित जीवन जी रहे हैं। साथ ही लेबनान से हिजबुल्ला के हमलों की वजह से भी लगातार खतरा बना हुआ है। इस्रा. इली नागरिक इसे सरकार की विफलता बता रहे हैं। करीब 130 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। ऐसे में बंधकों के परिजनों सरकार के खिलाफ मुखर होकर आलोचना कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की जांच के खिलाफ अमेरिका

अमेरिका ने सोमवार को कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की इस्राइल के खिलाफ जांच का विरोध करेगा।

दरअसल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इस्रा. इल के गाजा में की गई कार्रवाई की जांच करेगा।

इस्राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने यह मुद्दा उठाया था। अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रवक्ता केरीन जीन पिएरे ने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की जांच को लेकर स्पष्ट हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे।

हमें नहीं लगता कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास इसका अधिकार है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जांच में इस्राइली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आरोप लग सकते हैं।

अमेरिका ने कहा कि उनका फोकस युद्धविराम कराने और बंधकों की रिहाई पर है।

हम भीख मांग रहे और भारत महाशक्ति बनने की राह पर

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के शीर्ष नेता और जमीयत उलेमा ए इस्लाम (एफ) के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने भारत से पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा है कि भारत आज महाशक्ति बनने की राह पर है, जबकि हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। मौलाना ने पूछा कि इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद नेशनल असेंबली के पहले सत्र को संबोधित करने के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कही।

मौलाना ने कहा कि देश की दुर्दशा के लिए पर्दे के पीछे से फैसले लेने वाली अदृश्य ताकतें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जनता के चुने हुए प्रति. निधियों को कठपुतली बना दिया है। उन्होंने कहा कि यही ताकतें दीवारा. के पीछे से हमें नियंत्रित करती हैं। वही फैसले करती हैं, जबकि हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। पाकिस्तानी संसद की वैधता पर सवाल उठाते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि संसद सदस्यों ने सिद्धांतों को त्याग दिया है और वे लोकतंत्र को बेचने में जुटे हैं। क्या संसद हकीकत में लोगों के जनादेश को प्रतिबिंबित करती है? महलों में और नौकरशाहों द्वारा फैसला किया जाता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा।

देश में ठहराव आ गया है

मौलाना फजलुर रहमान ने पूछा कि कब तक हम समझौता करते रहेंगे? कब तक हम सांसद चुने जाने के लिए बाहरी ताकतों से मदद मांगते रहेंगे? उन्होंने 2018 और 2024 दोनों चुनावों में चुनावी धांधली की निंदा की। रहमान ने स्वतंत्र रूप से कानून बनाने में कानून निर्माताओं की कथित शक्तिहीनता पर अफसोस जताया। उन्होंने सवाल किया, इस सदन में बैठते समय हमारी अंतरात्मा कैसे साफ हो सकती है, क्योंकि हारने वाले और जीतने वाले दोनों संतुष्ट नहीं हैं। मौलाना ने कहा कि, हमने अपने देश को ठहराव का शिकार बना दिया है।

परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के भाई की जमीन जब्त, अब होगी नीलामी

बागपत लखनऊ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाई डॉ. जावेद मुशर्रफ की बागपत के कोताना में करीब दस बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति निदेशाल्य ने जब्त कर लिया है। अब उस जमीन की नीलामी कराई जाएगी। इसके साथ ही रटौल व टांडा में मौजूद शत्रु संपत्ति का सर्वे कराया जा रहा है, जिससे सभी को एक साथ नीलाम किया जा सके।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुर्शरफ के पिता मुशर्रफुद्दीन और माता बेगम जरीन कोताना गांव की रहने वाली थीं। कोताना में दोनों की शादी हुई थी। वह वर्ष 1943 में दिल्ली जाकर रहने लगे थे, जहां परवेज मुशर्रफ व उनके भाई डॉ. जावेद मुशर्रफ का जन्म हुआ था।

उनका परिवार वर्ष 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान में जाकर बस गया था। मगर दिल्ली के अलावा उनके परिवार की हवेली व खेती की जमीन कोताना में मौजूद थी। इसमें परवेज मुशर्रफ की जमीन बेच दी गई तो उनके भाई डॉ. जावेद मुशर्रफ की करीब दस बीघा खेती की जमीन बच गई। कोताना की हवेली उनके चचेरे भाई हुमायूं के नाम दर्ज हो गई थी। परवेज मुशर्रफ के भाई डॉ. जावेद मुशर्रफ की जमीन को शत्रु संपत्ति में दर्ज कर दिया गया था, जिसको अब जब्त करने की कागजी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जमीन का सर्वे किया गया, जिससे उसको नीलाम करने की तैयारी है।

शत्रु संपत्ति निदेशालय से हो रही कार्रवाई

पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाई डा. जावेद मुशर्रफ की जमीन को लेकर पूरी कार्रवाई लखनऊ से शत्रु संपत्ति निदेशालय से चल रही है। निदेशालय से पर्यवेक्षक मनोज कुमार सिंह टीम के साथ कुछ दिन पहले कोताना पहुंचे और वहां का सर्वे किया।

इसमें अब भू–लेख विभाग की टीम को लगाया गया, जो उसके पूरे कागजात तैयार करने में लगे हुए हैं।

स्वामी,सम्पादक,प्रकाशक व मुद्रकः संतोष कुमार शुष्टा, आकाश व्यू, छकड़ायल रोड, कमला नगर, संजौली शिमला हि0 प्र0 – 171006 से प्रकाशित तथा सिग्मा प्रिंटर बलॉक न.6,शॉप न.170 एसडीए कॉम्पलेक्स कसुम्पटी शिमला से मुद्रित। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र शिमला ही मान्य होगा। मोबाईलः 09418453928,9805192400 e-mail: aapkasaamna@gmail.com